## राष्ट्रीय तिसहन विकास योजना का कार्यान्वयन

1456. श्री चिन्द्रका प्रसाद विपाठी: क्या कृषि मंत्री यह बताने की हापा करेंगे कि:

- (क) क्या यह सच है कि विभिन्न राज्य सरकारें केन्द्रीय सरकार के सहयोग से राष्ट्रीय तिलहन विहास योजना को कार्यान्वित कर रही हैं ;
- (ख) यदि हां, तो सरकार ने ऐसे राज्यों को वांछित किस्म के बीज समय पर उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए हैं ;
- (ग) क्या यह सच है कि विभिन्न राज्यों में तिलहनों के न मिलने के कारण 1987 में खरीफ की फसल में तिलहनों का उत्पादन काफी कम हो जाने की सम्भावना है; ग्रीर
- (घ) क्या सरकार एक अधिनियम पारित करके एक ऐसी नीति अपनाने का विचार रखती है जिससे कि केन्द्रीय सरवार को विभिन्न राज्यों से बीज संकलित करने और फिर समस्त राज्यों को उनकी आवश्यकतानसार इन्हें समय पर उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी साँपी जा सके?

कृषि मंत्रालय में कृषि भ्रौर सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा): (क) जी, हां।

(ख) राज्य सरकारों को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि वे "प्रजनक बीजों" के लिये अपने मांग पत्र भारतीय ३षि धनसंघान परिषद्/राज्य ३षि विश्व-विद्यालयों को बिजाई से एकं वर्षे पहले प्रस्तत करें ताकि राज्य बीज निगम श्रीर राज्य विभागीय फार्मी द्वारा चलाये जाने वाले आधारों और प्रमाणित बीज उत्पादन कार्यक्रम के लिये पे पित माला में प्रजनक बीजों का उत्पादन किया जा सके। इससे राज्यों को राज्य स्तर पर

## किसानों की मांगे पूरी करने में मदद मिल्गी।

to Questions

- (ग) 1987 के दौरान खरीफ तिलहन उत्पादन में बहुत से तिलहन उत्पादक राज्यों में व्याप्त सूखे को व्यापक स्थितियों के कारण कमी आने की सम्भावना है, बीजों की अनुपलब्धता के कारण नहीं।
- (घ) जी, नहीं । ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

## स्प्रिकलरों की खरीद के लिये कुषकों को श्चन्दान

1457. श्री चिन्द्रका प्रसाद व्रिपाठी : क्या कृषि मंत्री 28 श्रगस्त, 1987 को राज्य सभा में तारांकित प्रक्रन 472 के दिए गए उत्तर को देखेंगे स्रीर यह बताने की इपा करेंगे कि :

- (क) क्या विभिन्न राज्यों में ह पकों को स्प्रिकलरों की खरीद के लिए अलग ग्रलग दरों पर ग्रनुदान दिए जाते हैं ;
- (ख) यदि हां, तो ये दरें क्या हैं ; ग्रीर
- (ग) क्या केन्द्र सरकार वृषकों को स्प्रिकलरों की खरीद करने के लिये एक समान दर पर ग्रनदान देने की कोई गोजना बनाने का विचार रखती 충 ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सह-कारिता विभाग में राज्य ं मंती (श्री धोगेन्द्र मकवाणा) : (क) से (ग) जहां तक भारत सरकार का संबंध हैं, दो पृथक योजनाएं चाल हैं, जिसमें अन्य बस्तुओं के साथ-साथ स्प्रिकल सैटों की खरीद करमे के संबंध में भी किसानों के लिए राज सहायता की व्यवस्था शामिल है। इन योजनात्रों में से प्रत्येक के अन्तर्गत सभी राज्यों के लिए एक समान दरें निर्धारित हैं।